

# पत्रकारिता के प्रमुख मूल सिद्धांत

पत्रकारिता के आधारभूत सिद्धांतों को अक्सर निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जाता है-  
सत्य और सटीकता-पत्रकार का प्राथमिक कर्तव्य तथ्यों की गहराई से पुष्टि करना और निष्पक्ष रूप से सच को सामने लाना है।

जवाबदेही- सत्ता, संस्थाओं और समाज के प्रभावशाली लोगों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराना।

स्वतंत्रता- पत्रकारिता को किसी भी बाहरी दबाव या प्रभाव से मुक्त रहकर जनहित में कार्य करना चाहिए।

जनहित-नागरिकों को स्वतंत्र और जागरूक समाज में कार्य करने के लिए विश्वसनीय और सटीक जानकारी प्रदान करना।

- बिल कोवाच और टॉम रोसेनस्टील ( पुस्तक 'द एलिमेंट्स ऑफ जर्नलिज्म' में )



भ्रष्टाचार और फासी शक्तियों के विरुद्ध शंखनाद

# नवयुग

R.N.I. No. 15990/67

संस्थापक संपादक: स्व. श्री चिरंजीव जोशी 'सरोज'

हिन्दी पाक्षिक

वर्ष-60 अंक-2

जयपुर, 30 जून, 2026

मूल्य- 10 रुपए

पृष्ठ- 8

## डेटा सेंटर्स की संभावित बाढ़..

पानी को तरसती मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा

इस पक्ष का विशेष सम्पादकीय विनोद जोशी द्वारा



पूरे विश्व में डेटा सेंटर उन क्षेत्रों में बन रहे हैं, जो पानी की किल्लत से पीड़ित हैं। भारत में अभी इस विषय पर युद्धस्तर पर कार्य हो रहा है, जबकि यह कटु सत्य है कि देश की तीन चौथाई आबादी इस समय पीने के पानी के लिए तरस रही है। हालात तब गंभीर हो जाते हैं जब यह मालूम चलता है कि भारत में डेटा सेंटरों में जल उपयोग को लेकर फिलहाल अनिवार्य पर्यावरण मानक या अनिवार्य रिपोर्टिंग के नियम मौजूद नहीं हैं। याने 'पूँजीपिशाचों' के लिए कोई नियम या कायदे नहीं हैं।

हर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर की स्थापना की खबर को भारत में एक बड़ी उपलब्धि समझा जाता है। इनसे विदेशी निवेश के रूप में आने वाले डॉलर की खबर उस समय और महत्वपूर्ण हो गई है, जब देश के सामने भुगतान संतुलन की चुनौती बढ़ रही है। मगर डेटा सेंटरों के साथ एक अन्य बड़ी समस्या भारत आ रही है। ये वो समस्या है, जिसके कारण डेटा सेंटरों विभिन्न अमेरिकी राज्यों में बेहद अलोकप्रिय हो गए हैं। इन सेंटरों के लिए पानी और बिजली की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती है कि उससे भविष्य बिगड़ने की आशंका से कई अमेरिकी राज्यों में ये सेंटर बड़े जन प्रतिरोध का कारण बने हुए हैं।

मगर भारत में इनको लेकर जागरूकता की अभी कमी है। जबकि गैर-सरकारी संस्था- कार्सिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में भारत के डेटा सेंटरों ने सालाना 150 अरब लीटर पानी की खपत की। इन सेंटरों की बढ़ती संख्या के कारण 2030 तक यह आंकड़ा 358 अरब लीटर पहुंचने का अनुमान है। डेटा सेंटरों का कई उन जिलों में विस्तार हो रहा है, जो पहले से पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में फिलहाल डेटा सेंटरों में पानी और बिजली के उपयोग को लेकर अनिवार्य पर्यावरण संरक्षण मानक या अनिवार्य रिपोर्टिंग संबंधी नियम मौजूद नहीं हैं।

अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट आदि जैसी अमेरिकी और रिलायंस एवं अडानी ग्रुप जैसी भारतीय कंपनियां डेटा सेंटरों के निर्माण से जुड़ी हुई हैं। आशंका है कि इनके रसूख को देखते हुए पानी और बिजली से संबंधित सख्त नियम बनाने को लेकर सरकार कतराएगी, जिसका भविष्य पर बहुत खराब असर होगा। गौरतलब है कि क्लोउड-लूप लिक्विड कूलिंग, इमर्सन कूलिंग और 45 डिग्री सेल्सियस लिक्विड कूलिंग जैसे सिस्टम आज मौजूद हैं, जिनसे डेटा सेंटरों में पानी की जरूरत घट सकती है। अतः डेटा सेंटरों में इनका इस्तेमाल अनिवार्य करने के नियम सरकार को बनाने चाहिए। पानी के दोबारा इस्तेमाल की अनिवार्यता भी लागू की जानी चाहिए। किसी नए डेटा सेंटर को मंजूरी पानी के वैकल्पिक इंतजाम और जल ऑडिट की शर्त के साथ ही दी जानी चाहिए।

# मोदी मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा से भाजपा में बेचैनी

कुछ बाहर, कुछ नए और कुछ के मंत्रालय में बदलाव

नई दिल्ली से राजनैतिक संवाददाता द्वारा

इन दिनों नई दिल्ली के राजनैतिक परिदृश्य पर मोदी मंत्रिमंडल में बदलाव की हवा और गर्म हो रही है। इन सब के बावजूद राजनैतिक पंडितों ने कुछ नामों को उछाल कर बहुत से राजनेताओं में बेचैनी पैदा कर दी है। चर्चा गर्म है कि धर्मप्रधान और हरदीप सिंह पुरी की मोदी कैबिनेट से छुट्टी हो सकती है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का मंत्रालय बदले जाने और रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को नया वित्तमंत्री बनाए जाने की सुगबुगाहट है। सूत्रों के मुताबिक, मोदी मंत्रिमंडल में ये बड़ा फेरबदल अगले कुछ हफ्ते में हो सकता है।

धर्मप्रधान, शिक्षा मंत्री

संघ और विद्यार्थी परिषद के बैकग्राउंड वाले धर्मप्रधान 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। अभी ओडिशा के संबलपुर से लोकसभा सांसद और पिछले 12 साल से मोदी सरकार में मंत्री। जुलाई 2021 से शिक्षा मंत्री हैं। इन्हें हटाए जाने की चर्चा सबसे ज्यादा घूम रही है। कहा जाता है कि धर्मप्रधान के शिक्षामंत्री रहते 5 बड़ी लापरवाहियां हुईं- 2026 में नीट पेपर लीक, सीबीएसई बोर्ड की कॉपी चेंकिंग में गड़बड़ी, यू जी सी इकट्री गाइडलाइन्स, 2024 में यूजीसी नेट पेपर लीक और 2020 में आई नई शिक्षा नीति के लागू होने में देरी। इसके चलते केंद्र सरकार बार-बार बैकफुट पर दिखी। उनके ऊपर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन भी खतरनाक साबित हो रहा है। सबसे बड़ा खतरा उन्हें ही बताया जा रहा है।

हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम मंत्री

1974 बैच के रिटायर्ड IFS अफसर हरदीप सिंह पुरी 2014 में भाजपा से जुड़े थे। दो बार राज्यसभा सांसद बने। सितंबर 2017 से केंद्रीय मंत्री हैं। अभी इनके पास पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय है।

उनकी सबसे बड़ी तकलीफ सेक्स स्कैंडल

एपस्टीन फाइल्स में उनका नाम जुड़ा होना है। फरवरी में कांग्रेस ने दावा किया कि 2014-17 के बीच पुरी ने जेफरी एपस्टीन से 62 ईमेल एक्सचेंज किए और 14 मीटिंग्स कीं। उन्हें हटाने की एक वजह उनकी उम्र भी हो सकती है। 74 साल के पुरी पिछले 9 साल से मंत्री हैं।

रवनीत सिंह बिट्टू, रेल राज्यमंत्री

पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस में तीन बार लोकसभा सांसद बने। मार्च 2024 में भाजपा से जुड़े। फिर राज्यमंत्री बने। अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा पहुंचे।

3 जून को बिट्टू ने अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में उतरने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा, मैंने लोकसभा और राज्यसभा में 17 साल पूरे कर लिए हैं। मैंने अपना सामान पैक कर लिया है और पंजाब जाने

लिए उनका पूरा फोकस संगठन और इलेक्शन मैनेजमेंट पर रहे।

हर्ष मल्होत्रा, सहकारिता राज्यमंत्री

2015-16 में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर बने। 2024 में पूर्वी दिल्ली से सांसद और मोदी कैबिनेट में राज्यमंत्री बने। मई 2026 में दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष बने।

भाजपा की एक व्यक्ति, एक पद की नीति के तहत 62 साल के मल्होत्रा को कैबिनेट से हटाया जा सकता है।

जॉर्ज कुरियन, अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री

जॉर्ज कुरियन सुप्रीम कोर्ट में वकील रहे हैं। जून 2024 में मोदी सरकार में राज्य मंत्री बने। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय का जिम्मा संभाला। अगस्त

2024 में मध्यप्रदेश से राज्यसभा पहुंचे।

23 जून को मोदी कैबिनेट के इकलौते ईसाई मंत्री कुरियन ने इस्तीफा दे दिया। इसकी एक वजह अप्रैल-मई में हुआ केरलम विधानसभा चुनाव भी है। भाजपा को

उम्मीद से कमतर नतीजे मिले। 65 साल के कुरियन ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन 'कंजिराप्पल्ली' सीट पर वे तीसरे नंबर पर रहे।

नए चेहरे चर्चा में

शक्तिकांत दास

तमिलनाडु कैडर के 1980 बैच के रिटायर्ड अखिल भारतीय सिविल सर्विस के अफसर रहे शक्तिकांत दास पीएम मोदी के प्रधान सचिव-2 हैं। आर्थिक मामलों के सचिव, राजस्व सचिव, 15वें वित्त आयोग के सदस्य, त20 शेरपा और 2018 से 2024 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार के बड़े आर्थिक फैसले- नोटबंदी और जी एस टी लागू करने में दास की अहम भूमिका रही। बतौर रिजर्व बैंक गवर्नर तीन बार

शेष पृष्ठ 2 पर



# विदेशी पर्यटकों की पसंद राजस्थान के किले-महल, धार्मिक आस्था ने भारतीयों को आकर्षित किया

## राजस्थान पर्यटन पर एक रिपोर्ट

पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान ने वर्ष 2026 की पहली तिमाही में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर देश और दुनिया के पर्यटकों की पहली पसंद बनने का प्रमाण दिया है। पिछले दिनों पर्यटन विभाग की ओर से जारी हुए आंकड़ों में जनवरी से मार्च 2026 के बीच राज्य में कुल 6 करोड़ 19 लाख 86 हजार 185 पर्यटक यात्राएं दर्ज की गईं। इनमें 6 करोड़ 12 लाख 87 हजार 727 घरेलू और 6 लाख 98 हजार 458 विदेशी पर्यटक शामिल रहे। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि राजस्थान में धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक धरोहर, संस्कृति और प्राकृतिक पर्यटन का अनूठा संगम लगातार पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है।

पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक दलीप सिंह राठौड़ ने बताया कि इस अवधि के आंकड़ों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू और विदेशी पर्यटकों की पसंद अलग-अलग रही। जहां देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं ने धार्मिक स्थलों को सबसे अधिक महत्व दिया, वहीं विदेशी पर्यटकों ने राजस्थान के किलों, महलों, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों और वन्यजीव अभयारण्यों को अपनी पहली पसंद बनाया।

## खाटूश्यामजी में देशी पर्यटक

घरेलू पर्यटन के आंकड़ों में सीकर स्थित खाटूश्यामजी मंदिर ने सबसे अधिक श्रद्धालुओं को आकर्षित किया। केवल तीन महीनों में यहां 68 लाख श्रद्धालु पहुंचे। दूसरे स्थान पर करौली का कैलादेवी मंदिर रहा, जहां 47.42 लाख पर्यटकों ने दर्शन किए। चित्तौड़गढ़ स्थित सांवलियाजी मंदिर करीब 28.70 लाख श्रद्धालुओं के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

इसके बाद पुष्कर, अजमेर शरीफ दरगाह और जैसलमेर के प्रमुख पर्यटन स्थलों ने भी बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित किया। खास बात यह रही कि जैसलमेर ने अकेले पांच पर्यटन स्थलों जैसलमेर किला, रामदेवरा, सम सैंड ड्यून्स, पटवों की हवेली और तनोट माता मंदिर के साथ शीर्ष दस घरेलू पर्यटन स्थलों में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व दर्ज कराया।

## विदेशी पर्यटकों की पसंद आमेर

विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद जयपुर का आमेर किला रहा, जहां तीन महीनों में 91,422 विदेशी पर्यटक पहुंचे। इसके बाद जंतर-मंतर, जोधपुर का मेहरानगढ़ किला, उदयपुर का सिटी पैलेस और सहेलियों की बाड़ी ने विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक आकर्षित किया।

वन्यजीव पर्यटन में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान

ने भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। वहीं जगदीश मंदिर (उदयपुर), आभानेरी की चांद बावड़ी, जोधपुर का जसवंत थड़ा और रणकपुर जैन मंदिर भी विदेशी पर्यटकों के पसंदीदा स्थलों में शामिल रहे। इससे स्पष्ट है कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटक राजस्थान की शाही विरासत, स्थापत्य

घरेलू पर्यटक- 6,12,87,727

विदेशी पर्यटक - 6,98,458

घरेलू पर्यटकों की पहली पसंद - खाटूश्यामजी, सीकर

विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद - आमेर किला, जयपुर



कला, संस्कृति और प्राकृतिक विविधता को करीब से अनुभव करना चाहते हैं।

## धर्मस्थल बने आकर्षण

पर्यटन विभाग के अनुसार राजस्थान में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन लगातार मजबूत हो रहा है। खाटूश्यामजी, कैलादेवी, सांवलियाजी, पुष्कर और अजमेर शरीफ जैसे स्थलों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से यह स्पष्ट है कि धार्मिक पर्यटन राज्य की पर्यटन अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ बन चुका है।

वहीं दूसरी ओर विदेशी पर्यटकों के लिए राजस्थान आज भी अपनी ऐतिहासिक धरोहर, शाही महलों, किलों, संग्रहालयों और वन्यजीव पर्यटन के कारण वैश्विक स्तर पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

राठौड़ ने कहा कि राजस्थान का पर्यटन अब केवल विरासत पर्यटन तक सीमित नहीं रहा है। धार्मिक, सांस्कृतिक, रेगिस्तानी, साहसिक और वन्यजीव पर्यटन एक-दूसरे के पूरक बनकर राज्य की पर्यटन अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। यही विविधता राजस्थान को देश ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रमुख पर्यटन गंतव्यों में मजबूती से स्थापित करती है।

## पहली तिमाही का रिपोर्ट कार्ड:

कुल पर्यटक यात्राएं - 6,19,86,185

शीर्ष 10 घरेलू स्थलों में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व - जैसलमेर (5 स्थल)

जनवरी-मार्च 2026 में घरेलू पर्यटकों की पहली पसंद

## देशी पर्यटकों का गणित:

1. खाटूश्यामजी सीकर 68,00,000
2. कैलादेवी मंदिर करौली 47,42,568
3. सांवलियाजी मंदिर चित्तौड़गढ़ 28,70,000
4. पुष्कर अजमेर 18,78,312
5. जैसलमेर किला जैसलमेर 16,86,330
6. रामदेवरा जैसलमेर 16,86,330
7. सम सैंड ड्यून्स जैसलमेर 15,96,200
8. पटवों की हवेली जैसलमेर 15,70,550
9. तनोट माता मंदिर जैसलमेर 15,01,000
10. अजमेर शरीफ दरगाह अजमेर 14,93,122

## जनवरी-मार्च 2026 में विदेशी

## पर्यटकों का आंकड़ा:

1. आमेर पैलेस, जयपुर- 91,422
2. जंतर-मंतर, जयपुर- 80,820
3. मेहरानगढ़ किला, जोधपुर- 38,834
4. सिटी पैलेस, उदयपुर- 36,850
5. सहेलियों की बाड़ी, उदयपुर- 34,480
6. रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान- 30,829
7. जगदीश मंदिर, उदयपुर- 30,550
8. चांद बावड़ी, आभानेरी- 29,030
9. जसवंत थड़ा, जोधपुर- 26,117

अजमेर हाई सेक्योरिटी जेल की सुरक्षा फिर बेनकाब

# डकैत जगन गुर्जर की जेल में दिनदहाड़े हत्या

## अपराध संवाददाता द्वारा

अजमेर। अजमेर की हाई सेक्योरिटी जेल में 29 जून की दोपहर को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। धौलपुर के कुख्यात और चंबल के खूंखार डकैत रहे जगन गुर्जर की जेल के भीतर



गला घोटकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि भरतपुर के कुलदीप जघीना हत्याकांड के आरोपी ने जगन गुर्जर की हत्या की है। हाईकोर बंदी दोनों एक ही बैरक में बंद थे। इस वारदात से पूरे पुलिस महकमे और जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और जेल प्रशासन के तमाम आला अधिकारी भारी जाबते के साथ मौके पर पहुंच गए हैं।

## पुलिस महकमे में हड़कंप

मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार दोपहर को जेल में जगन गुर्जर पर हमला किया गया, जहां प्रथम दृष्टया गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई। वारदात की सूचना मिलते ही अजमेर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगिड़, गणेश राम, डिप्टी नॉर्थ मनीष बडगुजर और सिविल लाइंस थाना प्रभारी शंभू सिंह शेखावत दलबल के साथ जेल पहुंचे। वहीं, जेल प्रशासन की ओर से हाई सेक्योरिटी जेल अधीक्षक पारसमल जांगिड़, अजमेर सेंट्रल जेल अधीक्षक और अनंतेश्वर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर स्थिति संभाल रहे हैं। वहीं न्यायिक अधिकारी भी जेल पहुंचे गए हैं। एफ एस एल और मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की टीमों ने घटनास्थल को खंगालना शुरू किया। हाई सेक्योरिटी जेल के भीतर वारदात की भनक लगते ही फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की टीमों को तुरंत मौके पर बुलाया गया। टीमों ने जेल और आसपास के पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में लेकर घटनास्थल से फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स और अन्य महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं।

## जगन गुर्जर एक किवंदती

राजस्थान में दहशत का पर्याय बना जगन गुर्जर धौलपुर जिले के डांग क्षेत्र के भवुतीपुरा का रहने वाला था। साल 1994 में उसके जीजा की हत्या हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए उसने गांव के ही एक आदमी की हत्या कर दी थी। फिर पुलिस से बचने के लिए अपनी पत्नी और तीन भाइयों के साथ मिलकर चंबल के बिहड़ों में शरण ली और खुद की गैंग बना ली। जगन ने सात साल तक राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले चंबल में खूब आतंक मचाया था।

जगन गुर्जर की हत्या राजनैतिक रूप से भी संवेदनशील विषय है। पूर्वी राजस्थान की जाति आधारित राजनीति में उठापटक की भी बड़ी संभावना है। पूर्वी राजस्थान ने पिछले दो तीन विधानसभा-लोकसभा चुनावों में कई बार रंग बदले हैं। राजनेता भले ही इसे नकारें, लेकिन यह कटु सत्य है कि वहां की राजनीति की धुरी मीणा और गुर्जर समुदायों के ध्रुवीकरण के आसपास ही घूमती रही है। इस दृष्टि से भी इस क्षेत्र की राजनीति में भी उठापटक, आरोप-प्रत्यारोप लगने स्वाभाविक हैं। सरकार और प्रशासन को इस क्षेत्र पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी।

## सीबीआई जांच की मांग

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस वारदात को लेकर प्रदेश की जेल सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया ड्र के जरिए पूरे घटनाक्रम में साजिश की आशंका जताते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मामले की तत्काल प्रभाव से सीबीआई जांच कराने की मांग की है। रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अजमेर की हाई सेक्योरिटी जेल में बंद डकैत जगन गुर्जर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु अत्यंत गंभीर घटना है। उन्होंने कहा कि यह घटना राजस्थान की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल की सुरक्षा व्यवस्था एवं जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े करती है।

# रोबोटिक तकनीक से हुआ राजस्थान का पहला सफल किडनी ट्रांसप्लांट:अलग ब्लड ग्रुप के बावजूद पत्नी ने दान की किडनी, मरीज को मिली नई जिंदगी

## जयपुर

जयपुर के सीके बिरला हॉस्पिटल में रोबोटिक तकनीक से राजस्थान का पहला सफल किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है।

अलग ब्लड ग्रुप (एबीओ-इनकम्पेटिबल) होने के बावजूद पत्नी ने पति के लिए किडनी दान की और रोबोट से सर्जरी की गई। इस सर्जनी का नेतृत्व सीनियर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉ.देवेंद्र के.शर्मा ने किया।

यह ट्रांसप्लांट बूंदी निवासी एंड स्टेज रीनल

डिजीज से पीड़ित मरीज पर किया गया, जो लंबे समय से डायलिसिस पर निर्भर था। मरीज की पत्नी ने किडनी दान करने की इच्छा जताई, लेकिन दोनों के ब्लड ग्रुप अलग थे। मरीज का ब्लड ग्रुप बी-पॉजिटिव, जबकि पत्नी का ए-पॉजिटिव था। इतना ही नहीं, दोनों का एचएलए (ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन) मैच भी शून्य था, जिससे यह ट्रांसप्लांट बेहद चुनौतीपूर्ण बन गया। डॉ. देवेंद्र शर्मा और उनकी टीम ने सर्जरी के दौरान पहले डोनर की किडनी को

लैप्रोस्कोपिक डोनर नेफ्रेक्टोमी तकनीक से निकाला गया। इसके बाद रोबोटिक असिस्टेड रीनल एलोग्राफ्ट ट्रांसप्लांट के जरिए नई किडनी मरीज के शरीर में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित की गई।

नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. शील भद्र जैन और डॉ. अश्विनी शर्मा ने ऑपरेशन से पहले और बाद में दवाओं तथा इम्यूनोसप्रेसन प्रोटोकॉल का सफल प्रबंधन किया, जिससे मरीज का शरीर नई किडनी को स्वीकार कर सका।

# पासपोर्ट पर विवाद

## मोदी सरकार नागरिकता के प्रश्न पर भ्रम क्यों बना रही है?

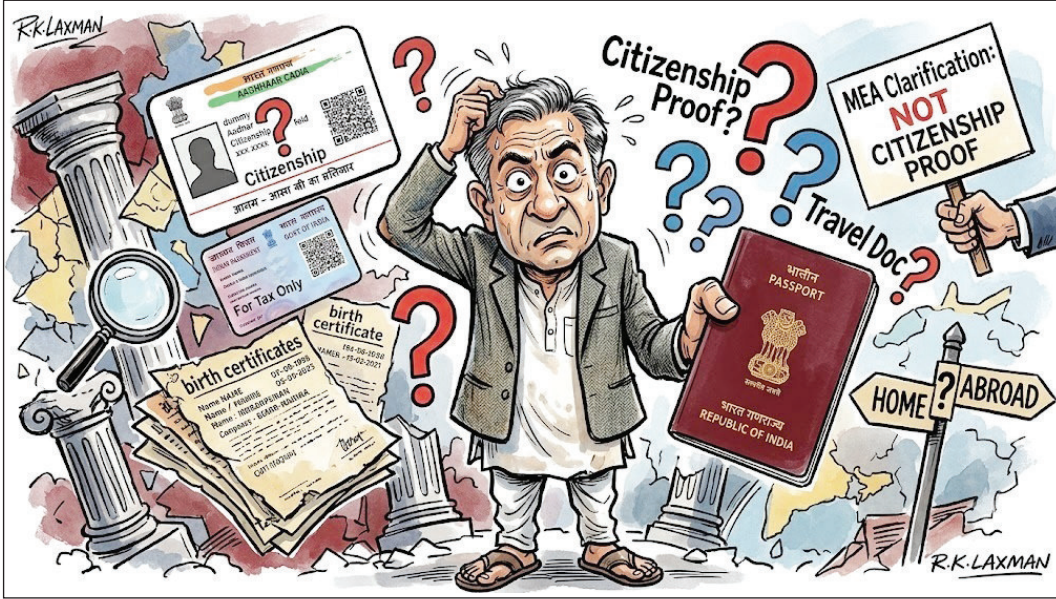
विनीत नारायण

अंतरराष्ट्रीय रूप से, पासपोर्ट राष्ट्रीयता का प्रतीक है, लेकिन यदि किसी की नागरिकता पर विवाद हो (जैसे आप्रवासन, आतंकवाद या दोहरी नागरिकता के मामले में), तो कोर्ट या सक्षम प्राधिकरण मूल दस्तावेजों- जन्म प्रमाण-पत्र, माता-पिता के दस्तावेज, प्राकृतिककरण प्रमाण आदि, की जांच करते हैं। भारत में यह स्थिति नई नहीं है; बॉम्बे हाईकोर्ट (2013) और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही रुख अपनाया है कि पासपोर्ट अकेला निर्णायक साक्ष्य नहीं है।

वास्तविकता को दोहराता है। पासपोर्ट नागरिकता नहीं बनाता, बल्कि सरकार की संतुष्टि पर आधारित होता है कि धारक भारतीय नागरिक है।

अंतरराष्ट्रीय रूप से, पासपोर्ट राष्ट्रीयता का प्रतीक है, लेकिन यदि किसी की नागरिकता पर

‘नागरिकता प्रमाण-पत्र’ नहीं होता; यह मुख्य रूप से प्राकृतिककरण या विशेष मामलों में ही जारी किया जाता है। यह बयान इसलिए अप्रासंगिक लगता है क्योंकि भारत में अधिकांश नागरिक जन्म-आधारित हैं। पासपोर्ट जारी करने से पहले गहन जांच होती है। इसे अचानक केवल



24 जून 2026 को पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के बयान ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज (ट्रैवल डॉक्यूमेंट) है, न कि नागरिकता का निर्णायक प्रमाण। इस बयान ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया, विपक्षी दलों ने इसे सत्ता पक्ष की ‘नागरिकता राजनीति’ से जोड़ा। जिससे आम नागरिकों के मन में भ्रम और आशंका पैदा हो गई। लाखों पासपोर्ट धारकों ने पूछना शुरू कर दिया, क्या हमारी नागरिकता पर सवाल उठ सकता है? यह विवाद क्यों और कब उठा और क्या यह विवाद खड़ा करना आवश्यक था?

इस विवाद की जड़ों को समझें। अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में पासपोर्ट की भूमिका का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि यह बयान वर्तमान भारतीय परिदृश्य में कितना प्रासंगिक या अप्रासंगिक है। साथ ही, यह कैसे अनावश्यक भ्रम पैदा कर रहा है और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पासपोर्ट को मुख्य रूप से यात्रा दस्तावेज माना जाता है, जो धारक की राष्ट्रीयता (नेशनलिटी) की पुष्टि करता है। वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस और अन्य अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत, पासपोर्ट जारी करने वाला देश यह गारंटी देता है कि धारक उसके क्षेत्र में लौट सकता है। यह दस्तावेज सीमा पार यात्रा, वीजा प्राप्ति और विदेश में सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है।

वहीं कई देशों में पासपोर्ट को नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए, अमेरिका में भी पासपोर्ट नागरिकता का प्राथमिक प्रमाण है, लेकिन यह जन्म, वंशानुगतता या प्राकृतिककरण जैसे आधारों पर निर्भर करता है। भारत में भी पासपोर्ट एक्ट, 1967 के तहत पासपोर्ट यात्रा के लिए जारी किया जाता है। विदेश मंत्रालय का बयान इस कानूनी

विवाद हो (जैसे आप्रवासन, आतंकवाद या दोहरी नागरिकता के मामले में), तो कोर्ट या सक्षम प्राधिकरण मूल दस्तावेजों- जन्म प्रमाण-पत्र, माता-पिता के दस्तावेज, प्राकृतिककरण प्रमाण आदि, की जांच करते हैं। भारत में यह स्थिति नई नहीं है; बॉम्बे हाईकोर्ट (2013) और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही रुख अपनाया है कि पासपोर्ट अकेला निर्णायक साक्ष्य नहीं है।

भारतीय नागरिकता संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 और नागरिकता अधिनियम, 1955 द्वारा निर्धारित होती है। नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण या क्षेत्र समावेशन से प्राप्त होती है। 1987 और 2004 के संशोधनों ने जन्म-आधारित नागरिकता को माता-पिता की नागरिकता पर निर्भर कर दिया। कोई एकल दस्तावेज (पासपोर्ट, आधार, वोटर आईडी या पैन) नागरिकता का पूर्ण प्रमाण नहीं है।

वर्तमान विवाद का संदर्भ विशेष गहन समीक्षा (एसआईआर) है, जो 16 राज्यों में मतदाता सूचियों की सफाई के लिए चल रही है। विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट वोटर सूची से बाहर किए गए व्यक्ति के खिलाफ चुनौती के लिए पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि यह यात्रा दस्तावेज है। यह बयान ‘सीएए-एनआरसी’ बहस, ‘डिटेक्ट-डिलीट-डिपोर्ट’ नीति और सीमा सुरक्षा के संदर्भ में आया है।

वास्तव में, यह कानूनी रूप से सही है, लेकिन व्यावहारिक रूप से अपर्याप्त। करोड़ों भारतीय पासपोर्ट धारक दैनिक जीवन में इसे अपनी भारतीयता का सबसे मजबूत प्रतीक मानते हैं। पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन, दस्तावेज जांच और जैवमितीय डेटा के बाद जारी होने वाला दस्तावेज है। सरकार के कई पोर्टल और फॉर्मस में अक्सर पासपोर्ट को नागरिकता के सबूत के रूप में स्वीकार किया जाता है। विपरीत रूप से देखा जाए तो आम नागरिकों के पास कोई

‘यात्रा दस्तावेज’ कहकर सरकार ने जनता को यह महसूस कराया कि उनकी भारतीयता ‘कागजी’ है, जबकि वास्तव में यह संवैधानिक अधिकार है।

देखा जाए तो यह विवाद अनावश्यक भ्रम का सबसे बड़ा उदाहरण है। आम आदमी सोच रहा है कि क्या उसका पासपोर्ट रद्द हो सकता है या ‘सीएए-एनआरसी’ जैसे अभियानों में इसे नजरअंदाज किया जाएगा? विपक्षी दल इसे मुस्लिम-विरोधी एजेंडे से जोड़ रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष इसे कानूनी स्पष्टीकरण बता रहा है। वहीं सोशल मीडिया की वायरल पोस्ट्स ने इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया, जिससे अप्रवासी भारतीय और युवा पीढ़ी में भी आशंका फैली। सवाल उठता है कि आधार, वोटर आईडी आदि भी निर्णायक नहीं हैं, तो क्या सबकी नागरिकता संदिग्ध है? यह सवाल लाखों लोगों के मन में घूम रहा है। परिणामस्वरूप, विश्वसनीयता का संकट पैदा हो गया है। जो दस्तावेज विदेश यात्रा और पहचान के लिए सबसे मजबूत है, उसे ‘अपर्याप्त’ बताकर सरकार ने खुद को घेर लिया है।

पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, यह कानूनी सत्य है, लेकिन संदर्भ से बाहर कहे जाने पर यह भ्रम का कारण बन जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह यात्रा दस्तावेज है, जबकि भारत में करोड़ों लोगों के लिए यह पहचान और गर्व का प्रतीक। वर्तमान विवाद अनावश्यक है क्योंकि यह मौजूदा कानूनी ढांचे को दोहराता है, लेकिन जनभावनाओं को नजरअंदाज करता है। सरकार को अब इस संकट को संवाद और स्पष्टता से दूर करना चाहिए। सरकार नागरिकों को आश्वस्त करें कि उनकी भारतीयता संवैधानिक है, न कि किसी दस्तावेज पर निर्भर है। ऐसा करने से एक मजबूत, पारदर्शी नागरिकता ढांचा न केवल भ्रम दूर करेगा, बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर और मजबूत बनाएगा।

पोलपट्टी

## घोटाले की खबरों से भरे अखबार

### खबरिया चैनलों से गायब खबरें!



आमतौर पर खबरिया चैनलों पर अब घोटालों की खबरें नहीं दिखाई जाती हैं। लेकिन अखबार अब भी ऐसी खबरें छाप रहे हैं। किसी भी दिन का अखबार खोलिए तो घोटाले ही घोटाले दिखेंगे। सोचें, 12 साल पहले 2014 में भाजपा का पूरा प्रचार अभियान तत्कालीन यूपीए सरकार के कथित घोटालों को लेकर था। ए टू जेड घोटाले की बात होती थी। भाजपा ने प्रचार किया कि कांग्रेस राज में आकाश से पाताल तक घोटाला हुआ है। उसी समय न खाऊंगा, न खाने दूंगा का नारा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलंद किया था। लेकिन आज जिधर देखिए, लोग सैकड़ों, हजारों करोड़ रुपए के घोटालों की खबरें आ रही हैं। पहले हुए घोटाले और उनकी जांच का मामला अलग है। इन सबका कॉमन कनेक्शन यह है कि ये सभी भाजपा शासित राज्य हैं।

इस समय जो घोटाले सबसे ज्यादा चर्चा में हैं उसमें एक अयोध्या का चढ़ावा चोरी का मामला है और दूसरी उज्जैन में जमीन खरीद का मामला है। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में कितने करोड़ रुपए चढ़ावा चोरी हुआ इसका कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है। लेकिन दो करोड़ रुपए की बरामदगी और कुछ सोना मिलने की खबर आई है। चोरी का आंकड़ा आठ करोड़ से लेकर कई सौ करोड़ रुपए तक का है। चांदी की दो सौ ईंट गायब हो गई या चांदी का काग भुसुडी गायब हो गया या निर्माण के समय भी गड़बड़ी हुई यह भी खबर आ रही है। लेकिन दो हफ्ते से ज्यादा बीत जाने के बाद तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और अब खबर है कि जिनके ऊपर आरोप लगे वे सब मंदिर में लौट आए हैं।

उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके परिवार की जमीन खरीद का मामला अलग तूल पकड़ रहा है। सीएम का परिवार पहले से रियल इस्टेट के कारोबार में है या कांग्रेस के नेता भी रियल इस्टेट के कारोबारी हैं, वाला दांव काम नहीं आ रहा है। पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव और उनके परिजनो ने 168 एकड़ जमीन उन्हीं इलाकों में कैसे खरीदी, जिन इलाकों में सरकारी विकास की परियोजनाएं आने वाली थीं, हाईवे बनने वाले थे या लैंड यूज बदला जाना था? ऐसा लग रहा है कि जैसे अयोध्या में किसी का कुछ नहीं हुआ वैसे ही उज्जैन में भी किसी का कुछ नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलावा हरियाणा, गुजरात, बिहार, दिल्ली कोई भी राज्य अछूता नहीं है। हरियाणा इन दिनों आईडीएफसी बैंक घोटाले में फंसा हुआ है। आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल गिरफ्तार हुए हैं। आरोप है कि 170 करोड़ रुपए का सरकारी फंड आईडीएफसी बैंक में ट्रांसफर किया गया और वहां से पैसे फर्जी खातों के जरिए निकाल लिए गए। राजधानी दिल्ली में सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी में साढ़े छह सौ करोड़ रुपए के घोटाले की जांच शुरू हुई है। मेडिकल उपकरण खरीदने में यह घोटाला हुआ है। राजेश एक्सपोर्ट का 15 लाख करोड़ रुपए का फर्जी काराबोर दिखा कर किए गए घोटाले की जांच भी अब शुरू हो गई है। बिहार में रिशु श्री घोटेला चल रहा है। कई आईएएस अधिकारी इसमें फंसे हैं। दो आईएएस अधिकारियों के यहां छापे पड़े हैं, जिनको निलंबित किया गया है और एक अधिकारी फरार हैं। गिरफ्तार रिशु श्री के मोबाइल से सरकार के गोपनीय दस्तावेज मिल रहे हैं। कैबिनेट नोटिंग्स मिल रही हैं। मंजूरी से पहले ही कैबिनेट की फाइल उसके यहां पहुंचने की जानकारी आ रही है। वह हजारों करोड़ रुपए के टेंडर मैनेज करता था। नीतीश कुमार की सरकार के समय बहुत अहम मंत्रालयों में रहे आईएएस अधिकारी उसके लिए काम करते थे। मंत्रियों की मिलीभगत का भी अभी खुलासा होना है।

# नेहरू-मोदी तुलना: बचकानी या क्षुद्र?

शंकर शरण

पंडित जवाहर लाल नेहरू और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना करना और नेहरू को मोदी से क्षुद्र दिखाने की चेष्टा दक्षिणपंथी ताकतों का आजकल पसंदीदा शगल है। हालांकि यह अलग बात है कि दोनों के कार्यकाल के कालखंड अलग हैं, दोनों के समय परिस्थितियाँ एकदम विरोधाभासी हैं और दोनों की विचारधारा और व्यक्तित्व अलग हैं। यह ध्रुव सत्य है कि नेहरू न सिर्फ अपनी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध थे, बल्कि अपने विरोधियों के प्रति स्वीकार्यता और आदरभाव को खुले में प्रदर्शित करते थे। इसके विपरीत नरेंद्र मोदी अपने कहे से पलट जाने में माहिर हैं और विरोधियों के प्रति सिर्फ अनादर नहीं बल्कि किसी हद तक नफरती भाव रखते हैं। याने नेहरू लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति आदरभाव प्रतिबद्धता के साथ रखते थे, यह चारित्रिक गुण नेहरू में था, मोदी में नहीं है। वे जो बात कहते थे, जो विश्वास रखते थे, उसी अनुरूप ही सारे काम आजीवन किए। मोदी ने अपने विचारों के प्रति वैसी निष्ठा शायद ही दिखाई। यदि नेहरू को हिन्दुत्व भाव से एलजी थी, तो उन्होंने नकली बातें नहीं की। उन्हें वामपंथियों से सहानुभूति थी, तो उन्होंने वामपंथियों को सम्मानित किया.. मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए बरसों तक अरुण शौरी जैसे से सलाह-मशवरा लेते रहने की छवि बनाई। पर जब राष्ट्रीय नीति-निर्माण और बौद्धिकों को प्रोत्साहन देने का समय आया, तो मोदी ने शौरी को बाहर, और सेक्यूलरवादी एम. जे. अकबर को पुरस्कृत किया।

अभी एक भाजपा नेता ने नेहरू-मोदी की तुलना करते हुए, तुलना में फजीहत ज्यादा की है। उन्होंने जिस तरह आड़ी-तिरछी बातें रखीं, उससे मोदी की भी फजीहत होती है।

जैसे, वे 15 अगस्त 1947 को 'माउंटबेटन द्वारा शपथ लेकर' नेहरू का प्रधानमंत्री बनना हल्का करते हैं, मानो कुछ अवैध हुआ। पर यह नहीं कहते कि मई 2014 में 'प्रणव मुखर्जी द्वारा शपथ लेकर' मोदी प्रधानमंत्री बने। क्या इसलिए कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने का श्रेय कांग्रेस नेता प्रणव मुखर्जी को भी जाएगा?

कुछ समय से प्रोपेगंडा चल रहा है कि मोदी सबसे अधिक समय प्रधानमंत्री रहने का 'रिकॉर्ड तोड़ देंगे'। यद्यपि नेहरू के लगभग 18 साल (यदि 2 सितंबर 1946 से जोड़ें, जिस का भाजपा नेता ने ही उल्लेख किया है), या लगभग 17 साल की तुलना में अभी मोदी के केवल 12 साल हुए हैं। तब यह रिकॉर्ड-तोड़ प्रोपेगंडा की उतावली क्यों? जबकि अभी 2029 का लोकसभा चुनाव भी बाकी है।

फिर, यह कैसा राष्ट्रवाद जिस में देश के सब से लोकप्रिय प्रधानमंत्री के पूरे काल को मानो अवैध बताने की झक है? भाजपा नेता ने नेहरू के प्रधानमंत्री बनने में 'अंग्रेजों की सुविधा' को भी कारण बताया, 'गाँधीजी की कृपा' को भी जोड़ा। पर वे भूल गये कि अक्टूबर 2001 में खुद मोदी भी वाजपेई की कृपा से मुख्यमंत्री बने थे। वरना, तब तक उन्हें कौन जानता था! बाद में भी, प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए स्वीकृत होने में भी मोहन भागवत की, फिर अरुण जेटली, अंततः राजनाथ सिंह की 'कृपाओं' का भी हाथ था। वरना वाजपेई, अडवाणी, जोशी, सुषमा, गडकरी जैसे निर्णायक नेता मोदी को दूर रखना चाहते थे। सो, यदि राजनाथ की कृपा न होती, तो मोदी प्रधानमंत्री उम्मीदवार ही नहीं हो सकते थे।

क्या नेहरू के साथ भी ऐसा कुछ था? वे 1920 के दशक से ही राष्ट्रीय नेता के रूप में प्रसिद्ध थे। चाहे 1947 में कांग्रेस कमिटी में उन से अधिक सरदार पटेल को चाहने वाले थे। जैसे 2013 में भाजपा कमिटी में आडवाणी को चाहने वाले अधिक थे। फिर, यदि 2013

में आम जनता में मोदी की हवा अधिक थी, तो 1946 में नेहरू विगत दो दशकों से लोकप्रिय थे — पटेल, सीतारामैया, कृपलानी आदि तुलना में काफी पीछे थे।

इस प्रकार, कभी पार्टी कमिटी, और कभी जनता में लोकप्रियता दिखाना अटपटा है।? जबकि दोनों हिसाब में नेहरू ऊँचे ठहरते हैं। तुलना करने में भाजपा नेता ने यह तथ्य गोल कर दिया है कि 2013 तक भी भाजपा के सर्वोच्च निकाय में मोदी को कितने वोट थे? यह भी कि तब वे उस निकाय के सदस्य तक नहीं थे।

जनता में भी मोदी इतने अनजान थे कि वाजपेई कृपा से मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन के लिए गुजरात में सुरक्षित सीट खोजनी पड़ी। जिस बड़ौदा में उन्होंने बरसों काम किया था, जिसे मोदी की 'कर्मभूमि' बताया गया, वहाँ से भी उन की जीत निश्चित न थी। सो वे 2002 में मणिनगर से विधायक बने।

क्या नेहरू के साथ भी ऐसा था? नेहरू पर 'गाँधी की कृपा' और 'अंग्रेजों की सुविधा' का लांछन लगाने वाले छिपाते हैं कि नेहरू देश की किसी लोक सभा सीट से जीत सकते थे — संभवतः बिना प्रचार किए भी! और यह स्थिति 1930 से 1960 तक मानी जा सकती है, यदि लोकप्रियता को आधार मानें।

यही नहीं, मोदी को 2014 में भी दो जगह से

उम्मीदवार बनने का खतरा था! फिर क्या होता, कहना कठिन है।

सो, नेहरू को नीचा दिखाने की कसरत अनावश्यक है। जिन्हें कभी तिकड़म नहीं करनी पड़ी। तब भी, जब गाँधी जी ने मार्च 1947 में नये वायसराय माउंटबेटन को सलाह दी कि जिन्ना के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बना दें ताकि भारत-विभाजन की बात खत्म हो जाए। पर पटेल, कृपलानी, आदि अन्य सर्वोच्च नेता भी जिन्ना को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में न थे।

अभी भाजपा नेता ने नेहरू की गलतियाँ दिखाने में अनुच्छेद 370, तिब्बत नीति, आदि मुद्दे भी उठाए हैं। वे भूलते हैं कि तब सरकार में पटेल, अंबेडकर, मुंशी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आदि अनेक दिग्गज थे। यदि कश्मीर या तिब्बत पर कोई गंभीर आपत्ति होती, तो वे विरोध करते या सरकार से अलग हो सकते थे। जैसा कि मुखर्जी ने अप्रैल 1950 में अन्य मुद्दे पर किया भी।

इसलिए, अब कश्मीर या तिब्बत को अकेले नेहरू के माथे डालना अतिरंजना है। निश्चित ही तब कांग्रेस नेतृत्व ने कश्मीर मुद्दे को हल्के से लिया था। बल्कि कांग्रेस कमेटी में अनुच्छेद 370 स्वीकार करने का प्रस्ताव सरदार पटेल ने रखा था! अतः बाद के

ईरान युद्ध रोकने में मध्यस्थता की।

जबकि नेहरू के समय भारत की हैसियत यह थी कि अमेरिका ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता देने की कार्रवाई (1955) शुरू कर दी थी। नेहरू का आत्मविश्वास ऐसा था कि उन्होंने उसे जोर देकर अस्वीकार किया। वह गलत कदम साबित हुआ, यह दूसरी बात है। पर अभी बात अंतरराष्ट्रीय राजनीति में देश व नेता की हैसियत की हो रही है।

अंदरूनी नीतियों में भी नेहरू ने शिक्षा, उद्योग, संस्कृति, आदि हर क्षेत्र में अपने विचारों के अनुसार काम किया। वे समाजवादी थे, तो उन्हीं मान्यताओं से विविध काम किए। जबकि मोदी ने केंद्र में आने से पहले और बाद में विपरीत अदाएं दिखाईं। पहले इन्होंने 'मिनिमम गवर्नमेंट' की बात की थी। जून 2012 में कहा गया था कि 'बिजनेस, व्यापार करना सरकार का काम नहीं है'। जबकि केंद्र में आने के बाद उन्होंने सरकार को बड़ा कर दिया। मंत्रालय घटने के बजाए बढ़ गया। हर कहीं सरकारी हाथ इतना बेतहाशा फैला दिया कि पहले कभी न था।

वही स्थिति सेक्यूलरिज्म पर देखी गई। इसमें मोदी की पब्लिक भंगिमा और असल नीति में भारी अंतर रहा है। प्रधानमंत्री बनने से पहले अपनी 'एंटी-मुस्लिम' छवि बनाकर लाभ लिया। जबकि वह पद लेकर मुस्लिमों के 'तुष्टिकरण' की घोषणा की।? उसी तरह, मुख्यमंत्री रूप में जैसे अधिकार उन्होंने अपने लिए रखे, वैसा अधिकार प्रधानमंत्री बनने पर भाजपा के किसी मुख्यमंत्री को नहीं दिया।

यह सब नीतिगत खालीपन दिखाता है। जो नेहरू में नहीं था। वे जो बात कहते थे, जो विश्वास रखते थे, उसी अनुरूप ही सारे काम आजीवन किए। मोदी ने अपने विचारों के प्रति वैसी निष्ठा शायद ही दिखाई। यदि नेहरू को हिन्दुत्व भाव से एलजी थी, तो उन्होंने नकली बातें नहीं की। उन्हें वामपंथियों से सहानुभूति थी, तो उन्होंने वामपंथियों को सम्मानित किया। प्रोत्साहन दिया।

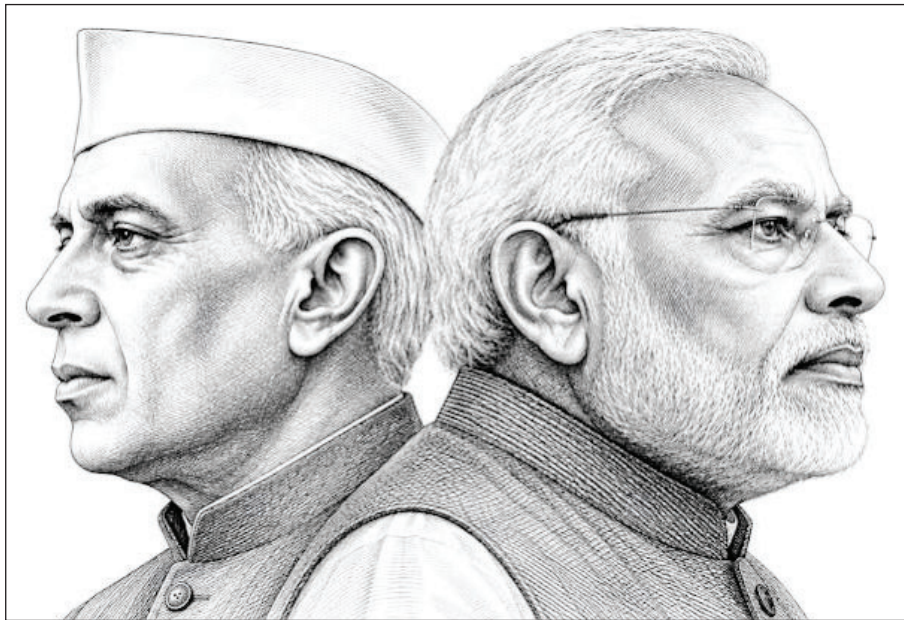
जबकि मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए बरसों तक अरुण शौरी जैसे की आवभगत की, उन से सलाह-मशवरा लेते रहने की छवि बनाई। पर जब राष्ट्रीय नीति-निर्माण और बौद्धिकों को प्रोत्साहन देने का समय आया, तो मोदी ने शौरी को बाहर, और सेक्यूलरवादी एम. जे. अकबर को पुरस्कृत किया। उन्हीं को बढ़ाया जिन्होंने मोदी राज के गुजरात को 'हिन्दुत्व की प्रयोगशाला' कह-कह कर वहाँ मुस्लिमों के उत्पीड़न का प्रचार किया था।

अतः जहाँ नेहरू में वैचारिक निष्ठा थी, वहीं मोदी का वैसा कुछ नहीं रहा है। इसीलिए नेहरू की पुस्तकें, उनकी 'आत्मकथा', 'भारत की खोज', आदि स्थायी महत्वपूर्ण बनी हुई हैं। जबकि मोदी के किसी भी लेखन या व्याख्यान को आज ही कोई नहीं देखता! तब कल उसका क्या मोल होगा, यह अनुमान कर सकते हैं।

यदि नेहरू ने नीतिगत गलतियाँ की, तब भी उन का स्थान स्टालिन, माओ, नासिर, आदि की श्रेणी में रहेगा जिन की अनेक नीतियाँ भी भयानक हानिकर साबित हुईं। लेकिन उनमें किसी दोहरेपन का दोष नहीं लगाया जा सकता।

जब बाद की पीढ़ियाँ नेताओं का मूल्यांकन करती हैं, तब पूरी स्थिति अधिक प्रामाणिक आती है। इस रूप में, अभी मोदी के मूल्यांकन का समय ही नहीं आया है। तब तक उनकी तुलना वर्तमान विदेशी नेताओं से करनी चाहिए, न कि अपने दिवंगत नेताओं से।

निस्संदेह, नेहरू की आलोचना के अनेक उचित बिंदु हैं। लेकिन ऐसी बचकानी विधि से भाजपा के प्रचारक ऐसा कर रहे हैं, उससे उलट मोदी की छवि ही गिरेगी।



चुनाव लड़ना पड़ा, क्योंकि किसी एक जगह जीत पक्की नहीं समझी गई थी। जबकि नेहरू मजे से एक ही फूलपुर से तीनों बार लोक सभा पहुँचे थे। उन्हें निजी सीट के लिए कभी सोचना भी नहीं पड़ा था।

सबसे बढ़कर, यदि 'जन' समर्थन को आधार बनाएं तो मोदी को 2024 में जनता ठुकरा चुकी है! उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। नेहरू की तीनों बार, 1952, 1957, 1962 में लोक सभा जीत उनके नेतृत्व में कांग्रेस की अकेले जीत थी। उन्हें अपने संसदीय दल का नेता चुने जाने के लिए भी कुछ नहीं करना पड़ा था। जो जून 2024 में मोदी के लिए करना पड़ा।

भाजपा संसदीय दल के नेता के रूप में मोदी का चुनाव 2014, 2019 लोक सभा चुनाव परिणाम के बाद जैसे हुआ था, वैसे 2024 में नहीं हुआ। पहले 5 जून 2024 को सहयोगी दलों द्वारा समर्थन की बैठक में उन्हें 'समर्थन' दिखाया गया। जिसका आधार बनाकर 7 जून 2024 को भाजपा संसदीय दल की बैठक में मोदी को नेता 'चुना' गया। यह भाजपा सांसदों पर मनोवैज्ञानिक दबाव था। वरना, भाजपा संसदीय दल की बैठक यदि कायदे से एनडीए समर्थन वाली बैठक से पहले होती, तब किसी अन्य भाजपा नेता द्वारा भी

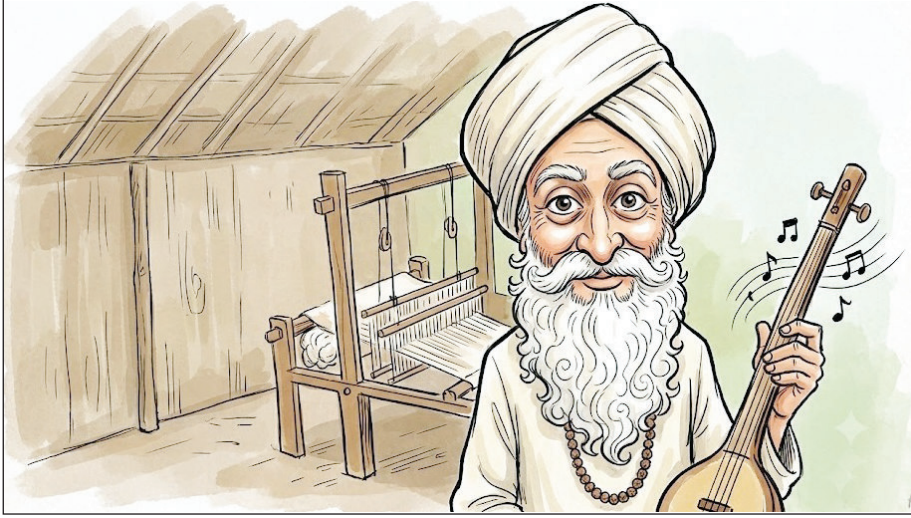
दुष्परिणामों का दोष अकेले नेहरू को देना छल है। यह वैसा ही होगा, जैसे 'नोटबंदी' (2016) या 'आपरेशन सिंदूर' (2025) की खामखाली का दोष भविष्य में केवल प्रधानमंत्री को दिया जाए।

दरअसल, नेहरू ही सच्चे राष्ट्रवादी थे। कांग्रेस की एकछत्र जीत के बाद भी उन्होंने राष्ट्रीय सरकार बनाकर उदाहरण पेश किया। अपनी कैबिनेट में डॉ. अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी रखा, जो उनकी पार्टी के नहीं थे। जब कि मोदी ने अपनी पार्टी के भी कई काबिल, बल्कि कठिन समय में सहायता करने वालों को भी छोड़ दिया। बल्कि अपमानित हाल में रखकर बाहर का रास्ता दिखाया। ऐसे कदमों से राष्ट्र की लाभ-हानि का हिसाब क्या बनता है?

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तो नेहरू का बड़ा स्थान था। वे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के एक संस्थापक थे, जिस ने तीन दशकों तक विश्व राजनीति में एक भूमिका निभाई। आज हमारा स्थान ट्रंप लगातार दिखा रहे हैं। उन्होंने भारत को मजाक बना दिया है जिन का मौखिक जबाब देने में भी हमारे नेता असहाय हैं। अमेरिका एक तरह जगजाहिर रूप से भारत को आदेश देकर कई फैसले करवा रहा है। तुलना में, पाकिस्तान की भी स्थिति इतनी ऊँची हुई है कि उस ने अभी अमेरिका-

कबीर दास जयंती पर विशेष

## कबीरदास खुद कहते हैं 'मेरी बोली पूरबी'



कबीर की मुख्य भाषा साधुक्रड़ी थी, जिसमें भोजपुरी, अवधी, ब्रज और राजस्थानी के शब्द मिलते हैं। लेकिन उनकी रचनाओं (विशेष रूप से भजनों और साखियों) में भोजपुरी की बोली, लय और शब्दावली का गहरा प्रभाव है। भोजपुरी अंचल में 'निर्गुण' कबीर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का सबसे लोकप्रिय माध्यम है। 'तोरी गठरी में लागे चोर', 'कवने ठगवा नगरिया लूटल हो', और 'भंवरवा के तोहरा संग जाई' जैसे उनके कई भजन भोजपुरी लोक संगीत की अमूल्य धरोहर हैं।

### कबीरदास जयंती

संत कबीरदास जी ने स्वयं अपनी भाषा के बारे में लिखा है, 'मेरी बोली पूरबी, हमें लख नहीं कोय, हमको तो सोही लखै जो धुर पूरब का होय'।

यहां 'पूरबी' से तात्पर्य पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोलियों, विशेषकर भोजपुरी से है।

संत कबीरदास भक्तिकाल के निर्गुण शाखा के महानतम कवि थे। उनकी विचारधारा और लोक साहित्य का भोजपुरी क्षेत्र और भाषा से गहरा संबंध रहा है। कबीर ने निराकार ब्रह्म की उपासना की, जिसे वे 'राम', 'साहेब' या 'अलख' कह कर पुकारते थे। उनके अनुसार, ईश्वर कोई मूर्ति या मंदिर में नहीं, बल्कि कण कण और हर मनुष्य के भीतर मौजूद है। उन्होंने सभी धर्मों और समाज में व्याप्त जात पात, कर्मकांड, अंधविश्वास तथा पाखंड का कड़ा विरोध किया।

यद्यपि कबीर की मुख्य भाषा साधुक्रड़ी थी, जिसमें भोजपुरी, अवधी, ब्रज और राजस्थानी के शब्द मिलते हैं। लेकिन उनकी रचनाओं (विशेष रूप से भजनों और साखियों) में भोजपुरी की बोली, लय और शब्दावली का गहरा प्रभाव है। कबीरदास जी ने संस्कृत जैसी कठिन भाषा का उपयोग करने के बजाय आम जनता की भाषा (भोजपुरी और अवधी के मिश्रित रूप) को माध्यम बनाया ताकि उनका संदेश सीधे जन-जन तक पहुंच सके। भोजपुरी अंचल में 'निर्गुण' कबीर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का सबसे लोकप्रिय माध्यम है। 'तोरी गठरी में लागे चोर', 'कवने ठगवा नगरिया लूटल हो', और 'भंवरवा के तोहरा संग जाई' जैसे उनके कई भजन भोजपुरी लोक संगीत की अमूल्य धरोहर हैं।

'कवने ठगवा नगरिया लूटल हो-  
काहे के ईट, काहे के पाथर, काहे के ई मटिया जुड़ल हो'?

यह कबीर का सबसे लोकप्रिय भोजपुरी निर्गुण भजन है। इसमें आत्मा (दुलहिन) परमात्मा के प्रति विरह और ज्ञान की बातें करती है।

'हंस अकेले चली जाए, भंवरवा के तोहरा संग जाई'

देहरी पकड़ि के मेहर रोवे, बांह पकड़ि के भाईभंवरवा के तोहरा संग जाई।

यह भजन मृत्यु की सच्चाई और आत्मा की यात्रा का सटीक वर्णन करता है।

इसी तरह 'तोरी गठरी में लागे चोर बटोहिया', 'भूल गई गोरी नैहर में सुख पाई के' जैसे अनेकों निर्गुण गीतों से भोजपुरी का भंडार महात्मा कबीर दास ने भरा है। वर्तमान में भोजपुरी गीत संगीत में जहां अश्लीलता और फूहड़ता का आरोप लगाया जाता है, ऐसे में कबीरदास जी की भोजपुरी, निर्गुण परम्परा भोजपुरी साहित्य की गंभीरता और उत्कृष्टता का बयान करती है।

कबीर की रचनाओं में आत्मा, परमात्मा का मिलन और सांसारिक मोह माया का त्याग जैसे विषय हैं, जो भोजपुरी निर्गुण लोकगीतों में पूरी तन्मयता के साथ गाए जाते हैं।

भोजपुरी क्षेत्र में कबीर की वाणी आज भी उतनी ही लोकप्रिय है, जितनी सदियों पहले थी। गांवों में होने वाले सत्संग, भजन कीर्तन और निर्गुण गायन में कबीर के पद प्रमुखता से गाए जाते हैं।

### भोजपुरी साहित्य पर कबीर का प्रभाव

भोजपुरी साहित्य में निर्गुण भक्ति धारा का विकास कबीर की प्रेरणा से हुआ। भोजपुरी के अनेक लोककवियों और गायकों ने कबीर की विचारधारा को अपनाया। उनके साहित्य में ईश्वर की निराकार सत्ता, मानव समानता, सामाजिक समरसता और आडंबर विरोध जैसे विषय प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं।

कबीर ने जात पात, ऊंच नीच और धार्मिक कट्टरता का विरोध किया। यही विचार भोजपुरी लोकगीतों और निर्गुण परंपरा में भी देखने को मिलते हैं। भोजपुरी के प्रसिद्ध निर्गुण गायकों ने कबीर के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया।

भोजपुरी अंचल में आज भी कबीर के दोहे और पद जीवन दर्शन का आधार माने जाते हैं। किसान, मजदूर, कारीगर और सामान्य ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों के बीच कबीर की वाणी से प्रेरणा लेते हैं। कबीरदास का जन्म काशी और निर्वाण मगहर में हुआ था, जो दोनों मुख्य रूप से भोजपुरी भाषी क्षेत्र हैं। विद्वान डॉ. मैनेजर पाण्डे, डॉ. राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी सहित कई साहित्यकार कबीर की मूल भाषा ठेठ भोजपुरी ही मानते हैं। कबीर को भोजपुरी का आदि कवि कहा जाता है।

## पंजाब में खिसकती सियासी ज़मीन के मायने

**पंजाब की राजनीति में हालिया मुद्दों के चलते विधानसभा चुनाव से कुछ माह पूर्व ही आम आदमी पार्टी के पक्ष में बना संतुलन हिल गया है। आरोपों से घिरे मुख्यमंत्री पलटवार कर रहे हैं, वहीं भाजपा पैठ बनाने की फिराक में है। अकाली दल अकेले दम बड़ी ताकत नहीं। बेशक फूट के बावजूद कांग्रेस का आधार है। क्या सीएम इन हालात से पार पा सकेगे?**

पंजाब की राजनीति में पिछला हफ्ता कुछ ज्यादा ही गर्म रहा। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन हाल ही में राज्य के दौरे पर थे; उन्होंने अमृतसर, लुधियाना व जालंधर का दौरा किया ताकि 2027 के शुरू में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले चुनौतियों की थाह ले सकें। जैसे ही नबीन पंजाब से लौटे, एक पुराना वीडियो सामने आया जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला कृत्य करते दिख रहे हैं, जिसने हर ओर हलचल मचा दी।

अकाल तख्त, जिसे व्यापक तौर पर आस्था के मामलों में सिखों द्वारा सर्वोच्च सत्ता माना जाता है, ने इस वीडियो को लेकर मान को दोषी ठहराया है; विपक्षी दलों ने भी ऐसा ही किया। मान ने अपने बचाव में भाजपा-शासित गुडुगांव की एक लैब से मिली 'क्लीन चिट' का हवाला दिया—परंतु, जल्द ही हरियाणा पुलिस ने क्लीन चिट की एवज में पैसे के लेन-देन के आरोप में उस लैब के दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

क्या मान इस संकट से उबर पाएंगे? क्या इससे 'आप' को बड़ा नुकसान होगा, वह पार्टी जिसने दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन-आंदोलन से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी या क्या पार्टी पिछले हफ्ते के झटके से उबरकर संकट को अवसर में बदल पाएगी? पिछले हफ्ते तक, ऐसा लग रहा था कि 'आप' आसानी से आगे बढ़ रही है और विपक्ष बिखरा पड़ा है, कोई दल गंभीर चुनौती पेश करने की स्थिति में नहीं। मुख्यमंत्री मान के बीच-बीच में शाम ढले होने वाले चुनावी दौरे शायद ही सतलुज नदी में तरंगें उठा पाए हैं (जिसमें अभी उफान नहीं आया था)। साथ ही, अरविंद केजरीवाल के मुफ्त सुविधाओं के चतुर वादों के साथ-जो लगता है भाजपा की सफल रही रणनीति की नकल है—जिसमें महिलाओं को पैसे देना (अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रु. प्रतिमाह तो अन्य को 1,000 रु.) और सफाई कर्मचारियों, स्कूल शिक्षकों व सरपंचों जैसे महत्वपूर्ण समूहों की शिकायतें दूर करने का वादा शामिल है, 'आप' एक ऐसा फॉर्मूला तैयार कर रही है जिसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। पंजाब सांसों थामे इंतजार कर रहा है और सवाल है कि क्या वीडियो से छिड़ी राजनीतिक लड़ाई इस सप्ताह भी जारी रहेगी।

पिछले हफ्ते तक, भाजपा को दौड़ में सिर्फ एक प्रतिभागी भर माना जा रहा था; लेकिन मचो उथल-पुथल के बीच, वह महसूस कर रही कि शायद सियासी ज़मीन पर पांव जम सकता है। महत्वाकांक्षा को सदैव लोगों को साथ जोड़ने वाली चीज माना जाता है, लेकिन सवाल है कि क्या यह काफी है? चुनाव में करीब छह माह बचे हैं, क्या भाजपा के पास विधानसभा की सभी सीटों पर लड़ने योग्य 117 उम्मीदवार हैं? गृह मंत्री अमित शाह और नितिन नबीन जैसे वरिष्ठ भाजपा नेताओं का तो मानना है कि हो जाएंगे। द ट्रिब्यून की ज़मीनी रिपोर्ट कहती है कि अकेले अपने दम पर न तो शिरोमणि अकाली दल और न ही भाजपा की स्थिति मजबूत है; हां, गठबंधन होने पर, मुकाबला करने लायक हो सकते हैं। मेरी सहयोगी अदिति टंडन ने हाल ही में एक वरिष्ठ भाजपा नेता का हवाला दिया है, जिन्होंने नाम न बताने की शर्त पर कहा है कि 'राजनीति में कुछ भी संभव है'। इसीलिए गत सप्ताह, जब पंजाब में सियासी परिदृश्य बदल रहा है, सवाल है—क्या भाजपा व शिरोमणि अकाली दल, जिनमें 2020 में मोदी सरकार के कृषि कानूनों को लेकर कटु अलगाव हुआ था, आखिर क्या फिर साथ आएंगे?

निश्चित तौर पर, 'राजनीति में एक हफ्ता बहुत लंबा समय होता है', यह एक ऐसी आम बात है जिसे हर राजनेता मानता है—सिवाय राहुल गांधी के, जिनके पास शायद अन्य ज्यादा ज़रूरी काम हैं, जबकि बीते हफ्ते ही दिल्ली में पंजाब के नए प्रदेशाध्यक्ष को लेकर अहम बातचीत बमुश्किल पूरी हो पाई। याद रहे, हाल ही में शहरी निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी, जिससे पता चलता है कि भले ही राज्य में पार्टी बंटी है—मुख्यमंत्री पद के कम से कम पांच दावेदार हैं—फिर भी कांग्रेस की विचारधारा के प्रति लोगों में थोड़ी-बहुत वफादारी अभी भी बची है।

अकाली दल के लिए बड़ी चुनौती है—क्या पंजाब के लोग उसे 'बेअदबी' के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने के लिए माफ़ कर पाएंगे? यह घटना 2015 में बरगाड़ी कस्बे में हुई थी, जब पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ने फटे मिले थे—तब अकाली सरकार थी।

निश्चित ही, पिछले हफ्ते विपक्ष भगवंत मान पर कथित वीडियो में वैसी ही गलती करने का आरोप लगा रहा है—जिसे मान और 'आप' जोरदार ढंग से नकार रहे हैं। इसीलिए आगामी दिन चुनाव प्रचार की चाल-ढाल तय करेंगे। क्या मुख्यमंत्री इस मुश्किल दौर से पार पा सकेंगे और अपनी बेगुनाही साबित कर पाएंगे? या क्या पंजाब 2027 में 'आप' के साथ वही करेगा जो उसने 2017 में अकाली दल के साथ किया था? 2027 की लड़ाई तो अभी शुरू ही हुई है। अकाल तख्त ने पहले ही आदेश दे दिया है कि पंजाब भर के ऐतिहासिक गुरुद्वारों में मान की निंदा वाले बैनर लगाए जाएं। कई जगह इस पर अमल हो भी गया; लेकिन ऐसी खबरें भी हैं कि कुछ स्वतंत्र प्रबंधन व सिंह सभा से जुड़े गुरुद्वारों में अभी ऐसा नहीं किया। स्थिति अभी भी साफ़ नहीं है।

एक और तथाकथित पार्टी है, वारिस पंजाब दे, जिसके सांसद अमृतपाल सिंह खड्डू साहिब सीट से तब चुने गए थे जब वे असम की जेल में थे व अभी वहीं हैं। पंजाब में हालात बदल रहे, नए माहौल में इस दल की स्थिति क्या होगी?



लंबा समय होता है', यह एक ऐसी आम बात है जिसे हर राजनेता मानता है—सिवाय राहुल गांधी के, जिनके पास शायद अन्य ज्यादा ज़रूरी काम हैं, जबकि बीते हफ्ते ही दिल्ली में पंजाब के नए प्रदेशाध्यक्ष को

लेकर अहम बातचीत बमुश्किल पूरी हो पाई। याद रहे, हाल ही में शहरी निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी, जिससे पता चलता है कि भले ही राज्य में पार्टी बंटी है—मुख्यमंत्री पद के कम से कम पांच दावेदार हैं—फिर भी कांग्रेस की विचारधारा के प्रति लोगों में थोड़ी-बहुत वफादारी अभी भी बची है।

अकाली दल के लिए बड़ी चुनौती है—क्या पंजाब के लोग उसे 'बेअदबी' के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने के लिए माफ़ कर पाएंगे? यह घटना 2015 में बरगाड़ी कस्बे में हुई थी, जब पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ने फटे मिले थे—तब अकाली सरकार थी।

निश्चित ही, पिछले हफ्ते विपक्ष भगवंत मान पर कथित वीडियो में वैसी ही गलती करने का आरोप लगा रहा है—जिसे मान और 'आप' जोरदार ढंग से नकार रहे हैं। इसीलिए आगामी दिन चुनाव प्रचार की चाल-ढाल तय करेंगे। क्या मुख्यमंत्री इस मुश्किल दौर से पार पा सकेंगे और अपनी बेगुनाही साबित कर पाएंगे? या क्या पंजाब 2027 में 'आप' के साथ वही करेगा जो उसने 2017 में अकाली दल के साथ किया था? 2027 की लड़ाई तो अभी शुरू ही हुई है। अकाल तख्त ने पहले ही आदेश दे दिया है कि पंजाब भर के ऐतिहासिक गुरुद्वारों में मान की निंदा वाले बैनर लगाए जाएं। कई जगह इस पर अमल हो भी गया; लेकिन ऐसी खबरें भी हैं कि कुछ स्वतंत्र प्रबंधन व सिंह सभा से जुड़े गुरुद्वारों में अभी ऐसा नहीं किया। स्थिति अभी भी साफ़ नहीं है।

एक और तथाकथित पार्टी है, वारिस पंजाब दे, जिसके सांसद अमृतपाल सिंह खड्डू साहिब सीट से तब चुने गए थे जब वे असम की जेल में थे व अभी वहीं हैं। पंजाब में हालात बदल रहे, नए माहौल में इस दल की स्थिति क्या होगी?

# मादक पदार्थों का दुरुपयोग और अवैध तस्करी मानवता के लिए खतरा

## सामाजिक संवाददाता की रिपोर्ट

नशीली दवाओं का बढ़ता प्रचलन आज विश्व मानवता के सामने एक ऐसे संकट के रूप में उभर रहा है, जो केवल स्वास्थ्य की समस्या नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर वैश्विक प्रश्न बन चुका है। नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अवैध तस्करी लाखों लोगों के जीवन को अंधकार में धकेल रही हैं। विशेष रूप से युवा पीढ़ी इसका सबसे बड़ा शिकार बन रही है। यही कारण है कि प्रतिवर्ष 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ताकि विश्व समुदाय इस चुनौती के प्रति जागरूक हो, सामूहिक प्रयासों को सशक्त बनाए और एक नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हो। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 1987 को संकल्प संख्या 42/112 के माध्यम से इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य मादक पदार्थों के दुरुपयोग से मुक्त अंतर्राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैश्विक सहयोग और कार्रवाई को मजबूत करना है। इस दिवस के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि नशीली दवाओं की समस्या का समाधान केवल दंडात्मक उपायों से नहीं, बल्कि जनजागृति, सामाजिक-पारिवारिक रोकथाम, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक सहयोग से संभव है।

संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) ने वर्ष 2026 के लिए इस दिवस की थीम निर्धारित की है- “विश्वव्यापी नशीली दवाओं की समस्या: स्थायी मुद्दे, नई चुनौतियाँ, अभिनव समाधान”। यह थीम इस तथ्य को रेखांकित करती है कि नशे की गिरफ्त में आए व्यक्ति को अपराधी नहीं, बल्कि सहायता और उपचार की आवश्यकता वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। समाज, परिवार, सरकार और स्वास्थ्य संस्थाओं के समन्वित प्रयास ही उसे पुनः सामान्य जीवन की ओर लौटा सकते हैं। विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर नशीली दवाओं के उपयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है। अनुमानतः

विश्वभर में 30 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। इनमें से करोड़ों लोग नशे की लत के कारण गंभीर शारीरिक एवं मानसिक रोगों से पीड़ित हैं, लेकिन उपचार सुविधाओं तक उनकी पहुँच अत्यंत सीमित है। मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों से पीड़ित प्रत्येक आठ व्यक्तियों में से केवल एक को ही उपचार प्राप्त हो पाता है। यह स्थिति विश्व स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर चुनौती को उजागर करती है।

बीते कुछ दशकों में वैश्विक मादक पदार्थ बाजार का स्वरूप तेजी से बदला है। परंपरागत नशीले पदार्थों- अफीम, हेरोइन, गांजा, चरस और कोकीन के साथ-साथ अब सिंथेटिक ड्रग्स, फेंटानिल, मेथामफेटामाइन और विभिन्न रासायनिक नशीले पदार्थों का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। कृत्रिम नशीले पदार्थों के उत्पादन में कम लागत, तस्करी में कम जोखिम और अत्यधिक मुनाफे ने अवैध मादक पदार्थ उद्योग को और अधिक संगठित तथा खतरनाक बना दिया है। आज मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह आधुनिक तकनीक, डार्क वेब, क्रिप्टोकॉर्सेसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर नए उपभोक्ताओं, विशेषकर युवाओं और किशोरों, को अपना लक्ष्य बना रहे हैं। ऑनलाइन नेटवर्क और गुप्त डिजिटल लेन-देन ने नशीली दवाओं की उपलब्धता को पहले की अपेक्षा कहीं अधिक आसान बना दिया है। संगठित अपराध और मादक पदार्थों का यह गठजोड़ विश्व शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गया है।

नशीली दवाओं का दुरुपयोग मानव

शरीर की लगभग प्रत्येक प्रणाली को प्रभावित करता है। हृदय, यकृत, फेफड़े, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। दीर्घकालिक सेवन व्यक्ति को अवसाद, मानसिक असंतुलन, आत्महत्या की प्रवृत्ति, स्मृति ह्रास और व्यक्तित्व विघटन की ओर ले जाता है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार अफीम, हेरोइन, स्मैक, कोकीन और

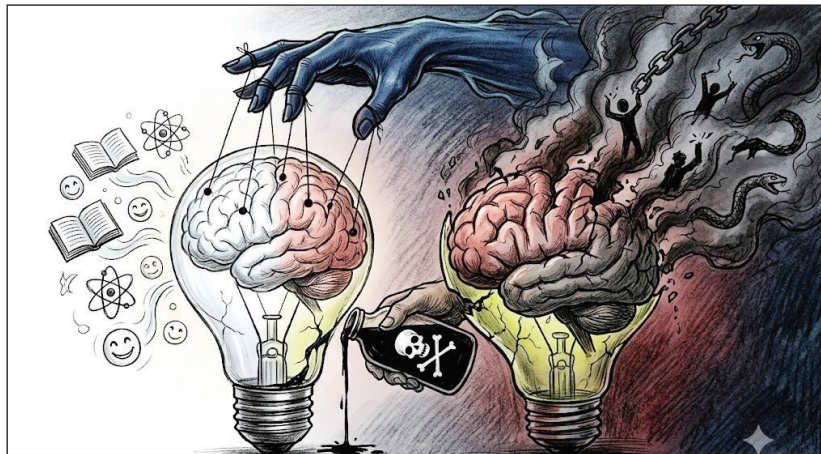
तथाकथित ‘गोल्डन क्रिसेंट’- अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान विश्व के प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्रों में शामिल हैं, जिसके कारण सीमावर्ती राज्यों में तस्करी की समस्या अधिक जटिल हो गई है। पंजाब लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी और नशे की समस्या से जूझ रहा है। सीमा पार से ड्रोन और अन्य माध्यमों से होने वाली तस्करी ने स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद की ही तरह नशे एवं ड्रग्स को व्यापक स्तर पर फैलाया है, जिसका उद्देश्य युवाओं को कमजोर और सामाजिक संरचना को

शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से तस्करी के नेटवर्क पर कार्रवाई की जा रही है। स्कूलों, कॉलेजों, पंचायतों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी से भी नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। फिर भी यह स्पष्ट है कि केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। परिवार, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक-सामाजिक संगठनों, मीडिया और नागरिक समाज को भी इस अभियान का सक्रिय भागीदार बनना होगा। बच्चों और किशोरों में जीवन मूल्यों, आत्मविश्वास, नैतिक शिक्षा और तनाव प्रबंधन की संस्कृति विकसित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। खेल, योग, ध्यान, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सकारात्मक सामाजिक वातावरण युवाओं को नशे की ओर बढ़ने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। महान दार्शनिकों और आध्यात्मिक चिंतकों ने सदैव संयम को स्वस्थ जीवन का आधार माना है। भारतीय संस्कृति का मूल संदेश भी आत्मसंयम, जागरूकता और सदाचार पर आधारित रहा है। यदि समाज में आध्यात्मिक चेतना, नैतिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं को पुनर्जीवित किया जाए तो नशे जैसी अनेक सामाजिक बुराइयों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि नशे के शिकार व्यक्तियों के प्रति घृणा या बहिष्कार का दृष्टिकोण छोड़कर उन्हें सहानुभूति, उपचार और पुनर्वास के अवसर प्रदान किए जाएं। नशे की जंजीरों को तोड़ने के लिए सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों, परिवारों और समुदायों को एक साझा मोर्चा बनाना होगा।

नशीली दवाओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि मानव जीवन अनमोल है और उसे नशे के अंधकार में खोने नहीं दिया जा सकता।

यदि हम एक स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, तो नशे के विरुद्ध संघर्ष को जनांदोलन का स्वरूप देना होगा। यही इस दिवस का मूल संदेश है और यही मानवता के उज्ज्वल भविष्य की अनिवार्य शर्त भी!

## अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस



सिंथेटिक ड्रग्स का निरंतर सेवन व्यक्ति को मानसिक रूप से अक्षम बना सकता है। नशे का दुष्प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। इसके कारण परिवार टूटते हैं, घरेलू हिंसा बढ़ती है, बेरोजगारी और आर्थिक संकट गहराते हैं तथा अपराध और सामाजिक असुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। अनेक शोधों में यह तथ्य सामने आया है कि चोरी, हिंसा, तस्करी, यौन अपराध और संगठित अपराधों का एक बड़ा हिस्सा मादक पदार्थों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ है।

भारत भी इस वैश्विक संकट से अछूता नहीं है। भौगोलिक स्थिति, सीमावर्ती चुनौतियाँ, बढ़ती शहरीकरण प्रक्रिया और युवाओं में बदलती जीवनशैली के कारण देश में नशीली दवाओं का दुरुपयोग चिंताजनक स्तर तक पहुँच चुका है। विशेष रूप से पंजाब, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा महानगरों में यह समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी है। भारत की पश्चिमी सीमा के निकट स्थित

क्षतिग्रस्त करना है। यह केवल कानून-व्यवस्था का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी प्रश्न है। जिसके दुष्परिणाम विशेषतः पंजाब के साथ-साथ समूचे देश को भोगने को विवश होना पड़ रहा है। पंजाब नशे की अंधी गलियों में धंसता जा रहा है, सीमा पार से शुरू किए गए इस छद्म युद्ध की कीमत पंजाब की जनता को चुकानी पड़ रही है, देर आये दुरस्त आये की भाँति लगातार चुनौती बने नशीली दवाओं एवं ड्रग्स के धंधे के खिलाफ आप सरकार ने एक महत्वाकांक्षी युद्ध एवं अभियान शुरू किया है। पंजाब देश में ड्रग्स में सर्वाधिक संलिप्त राज्यों में आता है। यह डाटा गतदिनों गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में ‘मादक पदार्थों की तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा’ पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में सामने आया।

भारत सरकार ने नशे के विरुद्ध अनेक पहलें शुरू की हैं। ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ देश के 272 से अधिक संवेदनशील जिलों में व्यापक जनजागरण,

## यमुना जल समझौता: राजस्थान-हरियाणा के बीच समझौता हुआ

# शेखावाटी को यमुना जल की राह खुलना तय

## नई दिल्ली संवाददाता की रिपोर्ट

दिल्ली के कर्तव्य भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुना जल समझौते से जुड़े मेमोरैंडम ऑफ़ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद थे। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि आज का दिन दोनों राज्यों के लिए एक बहुत अहम दिन है। एक ऐसा दिन जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा।

## पीएम मोदी का आभार - भजनलाल

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा यह समझौता दोनों राज्यों के लाखों लोगों और आने वाली पीढ़ियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। राज्य की जनता की ओर से, मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें बधाई देता हूँ।

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का हमेशा से यह मानना रहा है कि पानी सिर्फ एक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन और भविष्य की गारंटी है। मैं इसके

एक बड़े उदाहरण के तौर पर नर्मदा परियोजना का जिक्र करना चाहूंगा। जब हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब राजस्थान की ओर से यमुना के पानी की कोई औपचारिक मांग नहीं की गई थी। हालांकि, उन्होंने राजस्थान की स्थिति को देखते हुए एक परियोजना तैयार की। एक ऐसी स्थिति जिसे गुजरात और हरियाणा दोनों अच्छी तरह समझते थे। साथ ही यह पहचाना कि उस क्षेत्र से लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन मुख्य रूप से पानी के संकट के कारण हो रहा था। 2003 में हमारे बिना मांगे ही, प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बाड़मेर और जालौर जिलों के लिए नर्मदा का पानी आवंटित किया था।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा, ऊपरी यमुना बेसिन राज्यों के बीच यमुना के पानी के बंटवारे को लेकर 1994 में एक समझौता हुआ था। हालांकि, 32 वर्षों तक इसे लागू नहीं किया गया। पिछले कुछ वर्षों में इस मामले पर लगातार बातचीत और प्रयास किए गए हैं। हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बीच 17 फरवरी, 2024 को हुई बैठक में, भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पानी के हस्तांतरण के लिए एक संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया। 23 जून, 2026 को हुई बैठक के दौरान दोनों राज्यों के बीच परियोजना के कार्यान्वयन ढांचे पर सहमति बनी।

## ललित गर्ग

पुणे के लोहगढ़ किले की ऊंची पहाड़ी से मंगेतर केतन अग्रवाल को धक्का देकर हत्या करने के आरोप में सिया गोयल की गिरफ्तारी ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इससे पहले मेघालय में इंदौर के राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान कथित तौर पर पत्नी सोनम रघुवंशी द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर की गई हत्या की घटना ने भी समाज को स्तब्ध किया था। ये घटनाएं केवल अपराध की श्रेणी में रखकर भुला देने योग्य नहीं हैं। ये उन मूल्यों, विश्वासों और रिश्तों की बुनियाद पर गहरा आघात हैं, जिन पर भारतीय समाज सदियों से खड़ा रहा है। भारतीय संस्कृति में विवाह केवल दो व्यक्तियों का संबंध नहीं, बल्कि दो परिवारों, दो संस्कृतियों और दो जीवन-दृष्टियों का मिलन माना गया है। विवाह को सात जन्मों का बंधन कहा गया है। ऐसे में यदि कोई पति, पत्नी, मंगेतर या प्रेमी एक-दूसरे को जीवन का साथी मानने के बजाय बाधा और कांटा समझने लगे, तो यह केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना के संकट का संकेत है।

राजा रघुवंशी और केतन अग्रवाल जैसे मामलों में सबसे अधिक विचलित करने वाला पक्ष यह है कि हत्याएं उन लोगों ने कीं, जिन पर सबसे अधिक विश्वास किया गया था। विश्वास का यह टूटना ही समाज को भयभीत करता है। किसी भी सभ्यता की शक्ति उसकी सैन्य या आर्थिक ताकत नहीं, बल्कि उसके रिश्तों में निहित भरोसा होता है। जब यह भरोसा टूटने लगता है, तब समाज भीतर से कमजोर होने लगता है। यह प्रश्न स्वाभाविक है कि यदि कोई युवती या युवक किसी रिश्ते से संतुष्ट नहीं है, तो क्या उसके सामने 'ना' कहने का विकल्प नहीं था? आधुनिक समाज ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पर्याप्त स्थान दिया है। सगाई तोड़ना, विवाह से इनकार करना, आपसी सहमति से अलग होना—ये सभी वैधानिक और सामाजिक विकल्प उपलब्ध हैं। फिर हत्या जैसी भयावह मानसिकता क्यों जन्म ले रही है?

इस प्रश्न का उत्तर केवल कानून या पुलिस के पास नहीं है। इसके लिए समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, धर्माचार्यों और परिवार संस्थाओं को मिलकर मंथन करना होगा। आज का युवा एक ऐसे संक्रमणकाल से गुजर रहा है, जहां पारंपरिक मूल्य और आधुनिक जीवनशैली के बीच गहरा द्वंद्व मौजूद है। एक ओर परिवार की अपेक्षाएं हैं, दूसरी ओर व्यक्तिगत इच्छाएं। संवाद के अभाव में यह द्वंद्व कई बार मानसिक तनाव, विद्रोह और हिंसा का रूप ले लेता है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने श्रद्धा वालकर हत्याकांड, निक्की यादव हत्याकांड, बेंगलुरु, दिल्ली और अन्य महानगरों में प्रेम-संबंधों से जुड़े अनेक जघन्य अपराध देखे हैं। इन घटनाओं ने स्पष्ट किया है कि प्रेम, विवाह और संबंधों को लेकर समाज में गहरी अस्थिरता एवं अविश्वास बढ़ रहा है। यह अस्थिरता केवल स्त्री या पुरुष तक सीमित नहीं है, दोनों पक्षों में हिंसक प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं।

मोबाइल संस्कृति और डिजिटल संसार

ने इस संकट को और जटिल बनाया है। मोबाइल फोन, जो कभी दूरियों को समाप्त करने का माध्यम था, आज अनेक मामलों में षडयंत्र, छल और अपराध का साधन बनता जा रहा है। सोशल मीडिया ने तुलना,

रखना होगा। आज सबसे बड़ी चुनौती परिवार संस्था को पुनः सशक्त बनाने की है। संयुक्त परिवारों के विघटन, महानगरीय जीवन, एकाकीपन और अत्यधिक व्यस्तता ने परिवार के भीतर संवाद को कम कर

है। सभी धर्म प्रेम, करुणा, सत्य, अहिंसा और सह-अस्तित्व का संदेश देते हैं। यदि धार्मिक संस्थाएं युवा पीढ़ी को मानवीय मूल्यों, आत्मसंयम और संवाद की संस्कृति से जोड़ें, तो अनेक सामाजिक विकृतियों

तकनीकी प्रगति और आर्थिक समृद्धि से नहीं होती उसकी पहचान इस बात से होती है कि वहां लोग एक-दूसरे पर कितना भरोसा करते हैं। यदि भरोसा टूट गया, तो समाज की आत्मा घायल हो जाएगी। इसलिए आज का सबसे बड़ा राष्ट्रीय दायित्व है—रिश्तों के भरोसे को बचाना, मानवीय संवेदनाओं को पुनर्जीवित करना और प्रेम, विश्वास तथा सौहार्द की उस परंपरा को मजबूत करना, जिसने भारतीय समाज को सदियों से जीवंत बनाए रखा है।

आज भारतीय समाज जिस संक्रमणकाल से गुजर रहा है, उसमें रिश्तों का संकट केवल पति-पत्नी अथवा प्रेम-संबंधों तक सीमित नहीं रह गया है। एक ओर पुणे और मेघालय जैसी घटनाएं भरोसे के रिश्तों की हत्या कर रही हैं, तो दूसरी ओर प्रशासनिक लापरवाही के कारण अस्पतालों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों पर आगजनी एवं दुर्घटनाओं में मासूमों की मौतों व्यवस्था के प्रति जनता के विश्वास को तोड़ रही हैं। सांप्रदायिक तनाव, धार्मिक कट्टरता, पहचान छिपाकर बनाए जाने वाले संबंध, प्रेम के नाम पर छल और शोषण जैसी घटनाएं भी सामाजिक सौहार्द की नींव को कमजोर कर रही हैं। भौतिकता, उपभोक्तावाद और अंधी प्रतिस्पर्धा की आंधी ने संयम, सादगी, त्याग और पारिवारिक मर्यादाओं जैसे जीवन-मूल्यों को हाशिए पर धकेल दिया है। वहीं नशे का बढ़ता प्रचलन, शराब और मादक पदार्थों की लत युवा पीढ़ी को परिवार और समाज से काटकर हिंसा, अपराध और संवेदनहीनता की ओर ले जा रही है। जब समाज में व्यक्ति अपने स्वार्थ, वासना और तात्कालिक सुख को ही सर्वोच्च मानने लगे, तब रिश्ते साधना नहीं, सौदे बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि परिवार, शिक्षा, धर्म, मीडिया और शासन—सभी मिलकर मानवीय मूल्यों, पारदर्शिता, संवाद, नैतिकता और पारस्परिक सम्मान की संस्कृति को पुनर्जीवित करें। क्योंकि यदि मानवीय रिश्तों की बुनियाद ही हिल गई, तो न केवल परिवार टूटेंगे, बल्कि सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता और सभ्यता का पूरा ढांचा भी संकट में पड़ जाएगा।

# भरोसे के रिश्तों के कत्ल से ध्वस्त होता सामाजिक ढांचा



उपभोगवाद, त्वरित सुख और आभासी संबंधों को बढ़ावा दिया है। डिजिटल दुनिया में बने रिश्ते कई बार वास्तविक जीवन की जिम्मेदारियों और मर्यादाओं से कटे होते हैं। परिणामस्वरूप धैर्य, सहनशीलता और त्याग जैसी पारिवारिक जीवन की आवश्यक विशेषताएं कमजोर पड़ रही हैं। एक अन्य गंभीर पक्ष सांप्रदायिक अविश्वास और तथाकथित 'लव जिहाद' जैसे विवादों के संदर्भ में भी सामने आता है। जब प्रेम, विवाह या संबंधों का उपयोग छल, पहचान छिपाने, धार्मिक परिवर्तन, आर्थिक शोषण अथवा भावनात्मक उत्पीड़न के लिए किया जाता है, तब केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि समुदायों के बीच विश्वास का भी हनन होता है। यह आवश्यक है कि किसी भी प्रकार के संबंध पारदर्शिता, स्वेच्छा, समानता और ईमानदारी पर आधारित हों। पहचान छिपाकर, धोखे से अथवा किसी वैचारिक एजेंडे के तहत बनाए गए संबंध सामाजिक सौहार्द को चोट पहुंचाते हैं।

लेकिन इस विषय पर संतुलित दृष्टिकोण भी आवश्यक है। कुछ घटनाओं के आधार पर किसी सम्पूर्ण समुदाय को दोषी ठहराना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि सामाजिक सद्भाव के लिए भी घातक है। भारत की शक्ति उसकी विविधता और सांप्रदायिक सौहार्द में निहित है। सदियों से विभिन्न धर्मों, जातियों और संस्कृतियों के लोग यहां पारस्परिक सम्मान और विश्वास के आधार पर साथ रहते आए हैं। अतः किसी भी अपराध को अपराधी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी के रूप में देखना चाहिए, न कि पूरे समुदाय की पहचान के रूप में। हमें प्रेम के नाम पर छल का विरोध करना चाहिए, लेकिन साथ ही सामाजिक सौहार्द और मानवीय एकता को भी अक्षुण्ण

दिया है। माता-पिता और बच्चों के बीच संवादहीनता बढ़ रही है। बच्चों को भौतिक सुविधाएं तो मिल रही हैं, लेकिन भावनात्मक सुरक्षा और मूल्यपरक संस्कार कम होते जा रहे हैं।

विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में केवल रोजगारपरक शिक्षा पर्याप्त नहीं है। वहां जीवन-कौशल, नैतिक शिक्षा, भावनात्मक संतुलन, संबंध प्रबंधन और पारिवारिक मूल्यों पर भी गंभीर कार्य होना चाहिए। युवा पीढ़ी को यह समझाना होगा कि प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं—उत्तरदायित्व है, संबंध का अर्थ उपभोग नहीं—समर्पण है और मतभेद का समाधान हिंसा नहीं—संवाद है। धर्म और आध्यात्मिक संस्थाओं की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण

को रोका जा सकता है। आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद जैसे चिंतकों ने सदैव चरित्र, नैतिकता और आत्मानुशासन को समाज की आधारशिला माना। पुणे और मेघालय की घटनाओं ने हमें चेतावनी दी है कि यदि हम अभी नहीं चेते, तो रिश्तों का संकट और गहरा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम परिवार, समाज और राष्ट्र-तीनों स्तरों पर विश्वास की पुनर्स्थापना का अभियान चलाएं। परिवारों में संवाद बढ़े, युवाओं को निर्णय की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी का बोध कराया जाए, डिजिटल संस्कृति पर संयम हो और सामाजिक-सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत बनाया जाए। सभ्यता की पहचान ऊंची इमारतों,

## नए सत्र से पहले अक्षय पात्र ने संवारे सरकारी स्कूल

## जयपुर

नए शिक्षा सत्र की शुरुआत से पहले अक्षय पात्र संस्था ने राजस्थान के सरकारी स्कूलों को स्वच्छ, सुंदर और आकर्षक बनाने की विशेष पहल शुरू की है।

संस्था द्वारा प्रदेश के 11 जिलों के अनेक विद्यालयों में रंग-रोगन और



व्यापक साफ-सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिससे स्कूलों को नया कलेवर दिया जा रहा है। अक्षय पात्र संस्था अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में हमेशा अग्रणी रही है। बेहतर समाज के निर्माण के उद्देश्य से संस्था समय-समय पर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करती है।

इसी क्रम में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान विद्यालयों में कक्षाओं, दीवारों और पूरे परिसर का रंग-रोगन कर उन्हें नए सत्र के लिए तैयार किया जा रहा है।

## साफ-सुथरे स्कूल

### बच्चों के बेहतर भविष्य की पहली सीढ़ी

संस्था के स्टाफ की ओर से स्कूलों में विशेष सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों को स्वच्छ, सुरक्षित और सकारात्मक शिक्षण वातावरण मिल सके। संस्था का मानना है कि स्वच्छ और सुंदर विद्यालय ही बच्चों के बेहतर भविष्य की पहली सीढ़ी हैं। अक्षय पात्र की इस पहल को स्थानीय ग्रामीणों, स्कूल स्टाफ और अभिभावकों ने सराहा है। उनका कहना है कि यह अभियान न केवल स्वच्छता को बढ़ावा देगा, बल्कि बच्चों में विद्यालय के प्रति सकारात्मक माहौल और सीखने की प्रेरणा भी बढ़ाएगा।